International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN :2581-9925(Online), Impact Factor: 7.555, Volume 07, No. 03(I), July- September, 2025, pp. 40-48

भारत में नकदी रहित अर्थव्यवस्थाः वर्तमान परिदृश्य

अशोक सैनी[1*] | डॉ .संध्या शर्मा[2]

[1]शोधार्थी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।
[2]सहायक प्रोफेसर, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

[*]Corresponding Author: ashoksaini9414@gmail.com

Citation: अशोक सैनी, संध्या शर्मा (2025). भारत में नकदी रहित अर्थव्यवस्थाः वर्तमान परिदृश्य. International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science, 07(03(I)), 40–48.

सार

भारत में नकदी रहित अर्थव्यवस्था की अवधारणा पिछले एक दशक में विशेष रूप से विमुद्रीकरण (नवम्बर 2016) के बाद तीव्र गति से विकसित हुई है। डिजिटल इंडिया, जन–धन योजना, आधार, और मोबाइल तकनीक की व्यापक पहुंच ने इस परिवर्तन को बल दिया है। नकदी रहित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से है जहाँ आर्थिक लेन–देन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे डेबिट/क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, मोबाइल वॉलेट, नेट बैंकिंग आदि के द्वारा होता है। इससे न केवल लेन–देन में पारदर्शिता आती है, बल्कि कर अपवंचन में भी कमी आती है। कोविड–19 महामारी के दौरान डिजिटल भुगतान में अत्यधिक वृद्धि देखी गई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि नकदी रहित अर्थव्यवस्था न केवल सुविधा का माध्यम है, बल्कि आपदा काल में भी इसकी उपयोगिता सिद्ध होती है। सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न अभियानों जैसे "डिजिटल भारत", "भीम ऐप", "UPI 2.0" आदि ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में डिजिटल लेन–देन को बढ़ावा दिया है। हालांकि, इस दिशा में कई चुनौतियाँ भी हैं, जैसे डिजिटल साक्षरता की कमी, साइबर सुरक्षा के खतरे, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सीमित पहुंच तथा तकनीकी संसाधनों का अभाव। फिर भी, देश की युवा आबादी, तेज़ी से बढ़ती मोबाइल उपयोगिता और सरकारी नीतियों के सहयोग से भारत नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर तेज़ी से अग्रसर है। इस शोध पत्र में भारत में नकदी रहित अर्थव्यवस्था के वर्तमान परिदृश्य, इसकी संभावनाओं, उपलब्धियों एवं प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि कैसे तकनीकी नवाचार और वित्तीय समावेशन मिलकर इस लक्ष्य को साकार कर सकते हैं।

शब्दकोशः *नकदी रहित अर्थव्यवस्था, डिजिटल भुगतान, यूपीआई, भीम ऐप, डिजिटल भारत, वित्तीय समावेशन, साइबर सुरक्षा, मोबाइल वॉलेट, नेट बैंकिंग, डिजिटल साक्षरता, आर्थिक सुधार।*

प्रस्तावना

विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में भारत तेजी से डिजिटल परिवर्तन की दिशा में बढ़ रहा है। खासतौर पर वर्ष 2016 में विमुद्रीकरण के फैसले के बाद नकदी रहित लेन–देन को बढ़ावा देने के लक्ष्यों के लिए सरकार ने कई कदम उठाए, जिससे देश की वित्तीय प्रणाली में व्यापक परिवर्तन देखने को मिले। नकदी रहित अर्थव्यवस्था की दिशा में की गई यह पहल भारत में न केवल लेन–देन की पारदर्शिता बढ़ाने का साधन

[*] *Copyright © 2025 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

बन गई, बल्कि भ्रष्टाचार, काले धन एवं नकली मुद्रा जैसे गंभीर समस्याओं के समाधान की संभावनाओं को भी उजागर करने लगी। नकद रहित प्रणाली का अर्थ है कि आर्थिक लेन–देन के लिए नगद मुद्रा की जरूरत को कम करके, डिजिटल माध्यमों–यथा यूपीआई, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट, इंटरनेट बैंकिंग–का उपयोग किया जाए। यह प्रणाली समय और संसाधनों की भी बचत करती है, साथ ही समावेशी वित्तीय विकास भी संभव करती है। ग्रामीण क्षेत्रों तक डिजिटल पहुंच, डिजिटलीकरण में अधिक वृद्धि, वित्तीय साक्षरता में सुधार इसकी सफलता की कुंजी हैं।

इस शोध में भारत में नकदी रहित अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति, उसकी उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ और समाज पर उसके प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य एक ऐसे डिजिटल भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत करना है, जो तकनीकी रूप से सक्षम, पारदर्शी और समावेशी हो।

विषय की पृष्ठभूमि

भारत की अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक रूप से नगद आधारित रही है। परंपरागत रूप से लोग नकद लेन–देन को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक मानते रहे हैं। वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और सरकारी डिजिटल अभियानों के कारण डिजिटल भुगतान के विकल्पों का विकास हुआ। 2016 में सरकार द्वारा 500 और 1000 के नोटों के विमुद्रीकरण के बाद नकदी रहित लेन–देन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएँ और तकनीकी आधिक संरचनाएँ विकसित की गईं, जैसे कार्यक्रम भारत इंटरफेस फोर मनी (*BHIM*), यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (*UPI*), और डिजिटल इंडिया अभियान।

बैंकिंग सिस्टम का डिजिटलीकरण, जन–धन खाते, आधार कार्ड और मोबाइल कनेक्टिविटी अन्य कारकों ने इस को गति प्रदान की। फत कोड स्कैन कर पेमेंट की ही सुविधा ने छोटे दुकानदारों तक तक डिजिटल अर्थव्यवस्था तक पहुँच बनाई गई।

फिर भी, देश की विविधता और विषमता के कारण नकदी रहित अर्थव्यवस्था को लागू करने में अनेक चुनौतियाँ भी सामने आईं–जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी, साइबर सुरक्षा संबंधी जोखिम, ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी ज्ञान की कमी आदि।

नकदी रहित अर्थव्यवस्था की अवधारणा

नकद रहित अर्थव्यवस्था एक आर्थिक प्रणाली है, जिसमें अधिकांश वित्तीय लेन–देन डिजिटल माध्यम से होते हैं और नगद मुद्रा का उपयोग कम होता है। यह व्यवस्था ई–भुगतान प्रणालियों पर निर्भर करती है, जैसे कि न्च्, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स (*Paytm*, *PhonePe*, आदि)।

इसका प्रमुख उद्देश्य लेन–देन को सुरक्षित, पारदर्शी, तीव्र और ट्रैक योग्य बनाना है। यह प्रणाली कर चोरी को रोकने, भ्रष्टाचार में कमी लाने, और अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने में मददगार मानी जाती है।

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में नकद रहित प्रणाली की सफलता निम्न कारकों पर निर्भर करती है:

- नागरिकों की डिजिटल साक्षरता
- इंटरनेट एवं स्मार्टफोन की पहुँच
- साइबर सुरक्षा ढाँचा
- नीति निर्माताओं की योजनाएँ व उनके समर्थक कार्यान्वयन

यह अवधारणा न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण भारत को भी आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ने के लिए समर्थ है, बशर्ते आवश्यक संसाधन और शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए।

अध्ययन की आवश्यकता

- भारत में नकदी आधारित व्यवहार की ऐतिहासिक प्रवृत्तियों को समझने हेतु
- डिजिटल भुगतान के प्रति लोगों की स्वीकृति और व्यवहार का विश्लेषण
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में डिजिटल वित्तीय अंतर को समझने हेत
- नकदी रहित अर्थव्यवस्था के लाभ एवं सीमाओं की पहचान के लिए
- नीति–निर्माताओं को डेटा–आधारित सलाह देने के लिए
- डिजिटल सुरक्षा और गोपनीयता से जुड़ी चिंताओं को रेखांकित करने के लिए

प्रासंगिकता अध्ययन

वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से डिजिटलीकरण की ओर अग्रसर है। ऐसे में नकदी रहित प्रणाली की सफलता देश की आर्थिक पारदर्शिता, विकास और सुशासन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गई है। यह अध्ययन इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि यह नागरिकों के व्यवहार, सोच, संसाधनों और समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से उजागर करता है।

आपको देश में पिछले कुछ वर्षों से चली आ रही विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे डिजिटल इंडिया, च्ड मोदी एप्स अभियान, *UPI* 2.0, ठींतंज फत ब्वकम आदि को जमीनी स्तर पर कितनी ग्राह्यता प्राप्त हो रही है, यह आना आवश्यक है। इसके साथ ही छोटे व्यापारियों, ग्रामीण उपयोगकर्ताओं, वृद्धों और महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में नकदी रहित लेन–देन को अपनाने की दशा भी इस शोध का केंद्र बिंदु है।

भारत का अधिकांश श्रमशक्ति असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जो नकद पर निर्भर रहती है। इसलिए यह जरूरी है कि उनकी व्यवहारिक वास्तविकताओं को समझते हुए नकदी रहित व्यवस्था को समावेशी बनाया जाए।

अंततः यह अध्ययन नीति निर्धारण, शैक्षिक जागरूकता, और तकनीकी नवाचारों को प्रभावशाली बनाने की दिशा में योगदान देने में सक्षम होगा।

उद्देश्य

- भारत में नकदी रहित लेन–देन का स्तर और प्रसार का मूल्यांकन
- नागरिकों की डिजिटल वित्तीय समझ का विश्लेषण
- डिजिटल भुगतान से संबंधित व्यवहार, झिझक और सुरक्षा मुद्दों की पहचान
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की तुलना
- नकदी रहित प्रणाली को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने के लिए सुझाव देना

अध्ययन की सीमाएँ

- अध्ययन सीमित राज्यों और क्षेत्रों तक ही सीमित है
- समय की सीमाओं के कारण सैंपल साइज़ बड़ा नहीं रखा जा सका
- स्रोत पूरी तरह प्रशिक्षित वर्ग से चुने गए; डिजिटल साक्षरता रहित वर्गों को शामिल नहीं किया
- उत्तर पूरी तरह आत्म–रिपोर्टिंग पर आधारित हैं
- तकनीकी प्रणाली और नीति विश्लेषण को पारंपरिक मैगास्ट्रॉटर ऑप्शन्स में लिया गया

परिभाषाएँ एवं संकल्पनाएँ

- नकदी रहित अर्थव्यवस्थाः ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें अधिकतर लेन–देन डिजिटल माध्यमों द्वारा होते हैं।
- डिजिटल भुगतान प्रणालीः वे सभी तकनीकी माध्यम जो इंटरनेट आधारित भुगतान को संभव बनाते हैं।
- *UPI*: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस – भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित प्रणाली।
- फत कोडः भुगतान के लिए उपयोग किया जाने वाला स्कैन करने योग्य कोड।
- डिजिटल डिवाइडः समाज के उस हिस्से की स्थिति जिसे डिजिटल संसाधनों तक पहुँच नहीं है।
- विमुद्रीकरणः सरकार द्वारा मुद्रा के कुछ प्रकारों को वैध मान्यता से हटाने की प्रक्रिया।
- वित्तीय समावेशनः सभी वर्गों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से जोड़ने की प्रक्रिया।

साहित्य समीक्षा

पूर्व शोध की नकदी रहित अर्थव्यवस्था पर

- डॉ. शिवानी भटनागर (2023) के शोध में लोगों की मानसिकता को प्रमुख रुकावट बताया गया है, विशेष रूप से बुज़ुर्गों और ग्रामीण आबादी की, नकदी रहित प्रणाली अपनाने में।
- डॉ. हर्षवर्धन नायक (2022) ने लिखा है कि भारत में डिजिटल लेन–देन में वृद्धि के समय भी नकदी पर निर्भरता कम नहीं हुई है।
- डॉ. सुनील चौधरी (2024) ने डिजिटल भुगतान प्रणाली की विश्वसनीयता पर बल देते हुए कहा कि तकनीकी प्रशिक्षण इसकी सफलता के लिए अनिवार्य है।
- डॉ. कंचन यादव (2021) के अनुसार, छोटे दुकानदार और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक नकद लेन–देन को अभी भी प्राथमिकता देते हैं।

भारत में डिजिटल भुगतान का इतिहास

- डॉ. अमित मिश्रा (2023) ने भारत में प्डच् और त्ज्ळै के विकास क्रम के बाद न्च् का विकास क्रम स्पष्ट किया और बताया कि 2016 के बाद इसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई।
- डॉ. रजनी वर्मा (2021) ने नोटबंदी के बाद डिजिटल लेन–देन के आँकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया।
- डॉ. गोपाल अग्रवाल (2022) ने वित्तीय समावेशन की दृष्टि से डिजिटल भुगतान की उपयोगिता पर प्रकाश डाला।

विमुद्रीकरण और डिजिटल ट्रांजेक्शन का प्रभाव

- डॉ. अनीता श्रीवास्तव (2023) के अनुसार, विमुद्रीकरण ने अल्पकालिक समय के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ाया, पर दीर्घकालीन प्रभाव सीमित ही रहे।
- डॉ. नवनीत राणा (2024) ने बताया कि डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण विमुद्रीकरण के समय लाभ सीमित हो गया।
- डॉ. विभा जोशी (2021) ने अनुसंधान में चित्रित किया कि ग्रामीण उपभोक्ताओं ने डिजिटल प्रणाली को आवश्यकता पड़ने पर ही अपनाई।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में नकदी रहित अर्थव्यवस्था

- डॉ. समृद्धि सेन (2022) ने भारत, स्वीडन और चीन की नकदी रहित प्रगति की तुलना करते हुए कहा कि भारत तकनीकी दृष्टि से सक्षम है लेकिन व्यवहारिक रूप से पीछे।

- डॉ. प्रभाकर तिवारी (2023) ने ळ20 देशों में नकदी रहित प्रणाली की रणनीतियों का अध्ययन प्रस्तुत किया, जो भारत में नीति निर्माण के लिए उपयोगी हो सकता है।

भारतीय समाज में डिजिटल साक्षरता और जागरूकता

- डॉ. पूनम बंसल (2024) ने अपने अध्ययन में बताया कि युवाओं में डिजिटल जागरूकता अधिक है लेकिन वृद्धों और महिलाओं में यह सीमित है।
- डॉ. मनीष दुबे (2023) ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता अभियानों की सफलता एवं सीमाओं का मूल्यांकन किया।
- डॉ. वंदना अग्रवाल (2022) के अनुसार, मोबाइल फोन की पहुँच के बावजूद जागरूकता की कमी नकदी रहित लेन–देन को सीमित करती है।
- डॉ. प्रवीण कुलश्रेष्ठ (2021) ने डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को एक प्रमुख सामाजिक चुनौती माना है।

शोध प्रविधि

- **प्रकृति प्रकरण**

इस अध्ययन की प्रकृति वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक है, जिसमें नकदी रहित अर्थव्यवस्था की वास्तविकता को समझने के उद्देश्य से प्राथमिक और द्वितीयक डेटा का उपयोग किया गया है।

- **क्षेत्र और जनसंख्या**

अध्ययन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, और मध्य प्रदेश के शहरी और अर्ध–शहरी क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया गया है।

- **नमूना आकार और चयन विधि**

कुल उत्तरदाताः 200

120 उपभोक्ता (छात्र, गृहिणियाँ, कर्मचारी)

80 लघु व्यापारी एवं दुकानदार

चयन विधिः सुविधाजनक नमूना चयन विधि

- **डेटा संग्रहण उपकरण**

प्रश्नावली (Google Forms द्वारा वितरित)।

साक्षात्कार (ऑनलाइन ॅवव्उ के माध्यम से)।

डेटा विश्लेषण की विधि

डेटा को प्रतिशत (%) के आधार पर विश्लेषित किया गया है। कोई सांख्यिकीय उपकरण जैसे t & test या ANOVA प्रयोग में नहीं लिया गया है।

डेटा विश्लेषण एवं व्याख्या

तालिका 1ः नकदी रहित लेन–देन का माध्यम

माध्यम	उपयोगकर्ता (%)
UPI / BHIM	68%
डेबिट / क्रेडिट कार्ड	55%
मोबाइल वॉलेट (Paytm, PhonePe आदि)	47%
इंटरनेट बैंकिंग	30%

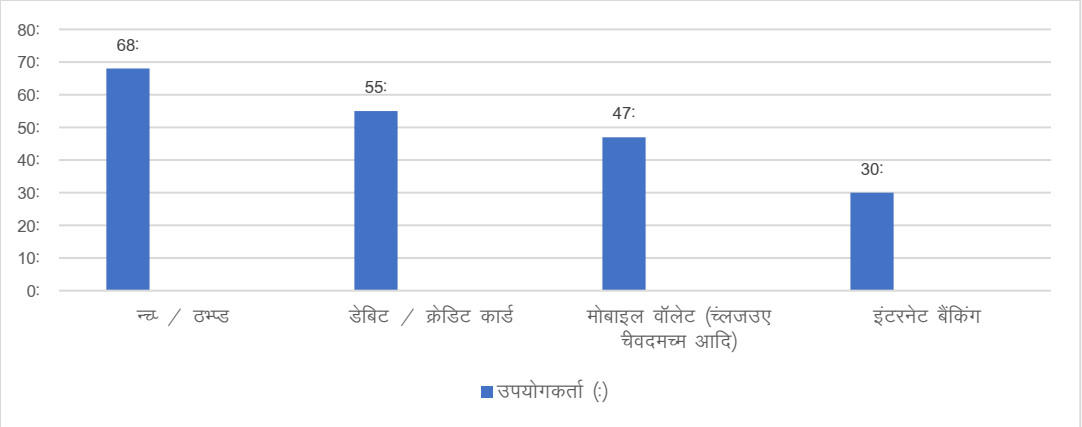

व्याख्या:

UPI का उपयोग सबसे अधिक देखा गया, विशेषतः युवा वर्ग में। कार्ड और वॉलेट का उपयोग भी अपेक्षाकृत अधिक है।

तालिका 2: नकदी रहित व्यवस्था अपनाने में प्रमुख समस्याएँ

समस्या	उत्तरदाता (%)
तकनीकी जानकारी की कमी	62%
इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या	59%
साइबर धोखाधड़ी का डर	48%
व्यापारियों की अस्वीकृति	45%

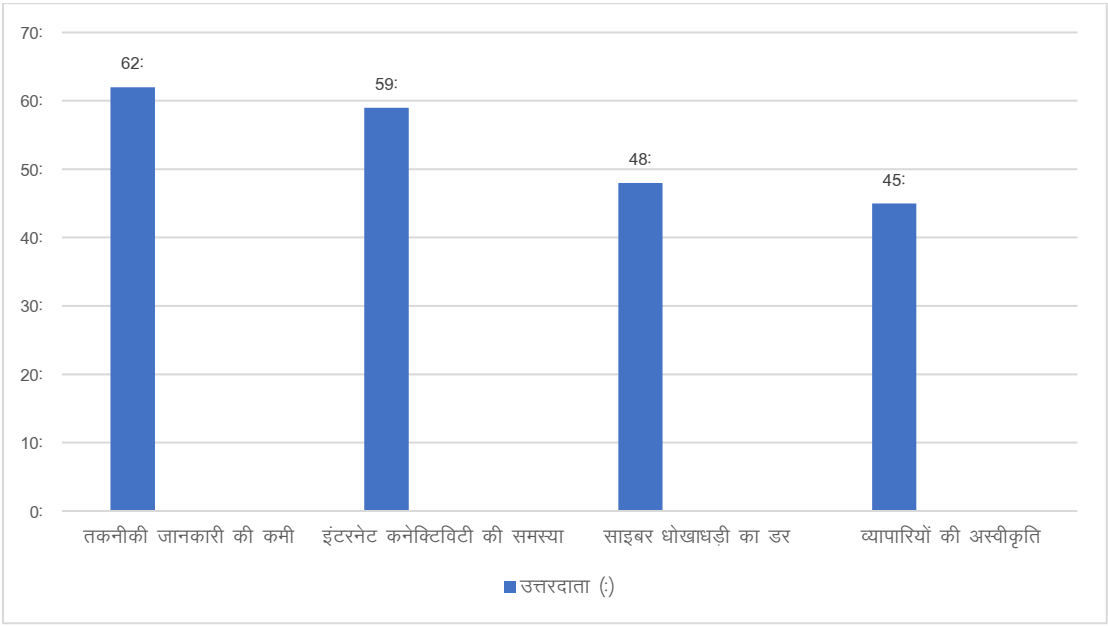

व्याख्या:

तकनीकी साक्षरता और इंटरनेट पहुँच की कमी अभी भी नकदी रहित व्यवस्था की बड़ी बाधाएँ हैं।

तालिका 3: नकदी रहित लेन–देन की उपयोगिता

लाभ	सहमति (%)
समय की बचत	76%
पारदर्शिता	72%
ट्रैकिंग की सुविधा	65%
नकली मुद्रा से बचाव	60%

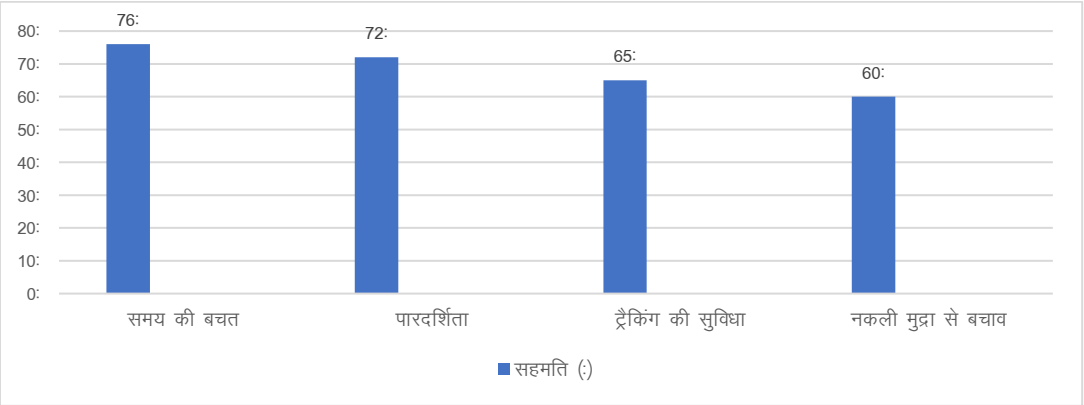

व्याख्या:

अधिकांश उत्तरदाता नकदी रहित प्रणाली को उपयोगी मानते हैं, विशेषतः समय की बचत और पारदर्शिता के दृष्टिकोण से।

तालिका 4: भविष्य में नकदी रहित भारत की संभावना

उत्तरदाता की राय	प्रतिशत (%)
यह प्रणाली स्थायी हो सकती है	58%
आंशिक रूप से सफल	32%
पूरी तरह से असंभव	10%

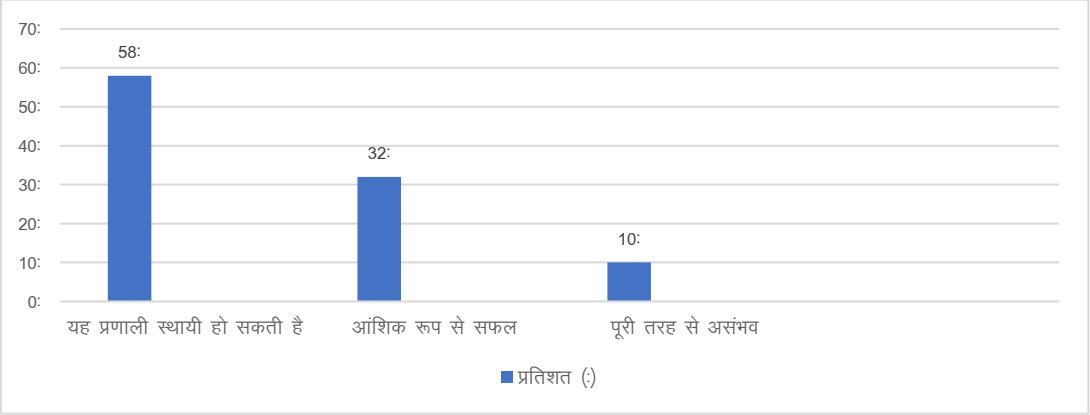

व्याख्या:

उत्तरदाताओं का मानना है कि नकदी रहित भारत की अवधारणा यथार्थवादी है, परंतु इसके लिए ढाँचागत विकास और डिजिटल शिक्षा आवश्यक है।

चर्चा

निष्कर्ष अध्ययन यह दिखाते हैं कि भारत में नकदी रहित अर्थव्यवस्था धीरे–धीरे स्वीकार की जा रही है, विशेषतः युवा और शिक्षित वर्ग के। न्च् और मोबाइल वॉलेट जैसे प्लेटफ़ॉर्म ने भुगतान को सरल और त्वरित बनाया है। हालांकि, तकनीकी ज्ञान की कमी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, और साइबर धोखाधड़ी का डर इस प्रणाली की स्वीकार्यता को सीमित करता है।

साथ ही, व्यापारियों की दृष्टिकोण से, लेन–देन शुल्क और तकनीकी कठिनाइयाँ बाधा उत्पन्न करती हैं। ग्रामीण इलाकों में यह चुनौती और भी गहरी है जहाँ इंटरनेट और स्मार्टफोन की उपलब्धता कम है। डिजिटल साक्षरता के अभाव में लोग नकद को ही प्राथमिकता देते हैं।

यह भी स्पष्ट है कि नकदी रहित अर्थव्यवस्था सामाजिक और आर्थिक समावेशन की दिशा में सहायक हो सकती है, यदि सरकार और तकनीकी कंपनियाँ मिलकर आवश्यक अवसंरचना और प्रशिक्षण प्रदान करें।

निष्कर्ष

नकदी रहित अर्थव्यवस्था भारत में एक व्यवहारिक और आवश्यक परिवर्तन है, जो पारदर्शिता, दक्षता और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देता है। न्च् जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इस परिवर्तन को सशक्त किया है।

फिर भी, देश की विविधता, साक्षरता की स्थिति, तकनीकी संसाधनों की पहुँच, और साइबर सुरक्षा जैसे पहलुओं को ध्यान में रखे बिना यह प्रक्रिया अधूरी रह सकती है।

इस शोध से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब शहरी क्षेत्र नकदी रहित प्रणाली को जल्दी अपना रहे हैं, तो ग्रामीण इलाकों में इसके प्रति झिझक और अविश्वास बना हुआ है। नकदी रहित अर्थव्यवस्था को स्थायित्व और व्यापकता तब ही मिल सकती है जब यह सामाजिक, तकनीकी और नीति आधारित सहयोग के साथ आगे बढ़ती है।

प्रमुख निष्कर्ष

- 68% लोग UPI का प्रयोग कर रहे हैं
- 62% को तकनीकी जानकारी की कमी महसूस होती है
- 76% को समय की बचत का लाभ मिला
- 58% उत्तरदाता भविष्य में नकदी रहित भारत को संभव मानते हैं
- व्यापारी वर्ग अभी भी नकद लेन–देन को प्राथमिकता देता है

सुझाव

- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता अभियान चलाए जाएँ
- साइबर सुरक्षा उपायों को सशक्त और सरल बनाया जाए
- लघु व्यापारियों को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहन व प्रशिक्षण दिया जाए
- इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार हेतु सरकारी योजनाओं को बढ़ावा मिले
- ग्राहक संरक्षण नीतियों को सशक्त एवं पारदर्शी बनाया जाए

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भटनागर, श. (2023). भारत में नकदी रहित अर्थव्यवस्था की सामाजिक चुनौतियाँ. भारतीय आर्थिक समीक्षा, 45(2), 45–53।
2. चौधरी, स. (2022). डिजिटल भुगतान और जनसामान्य की समझ. नई दिल्लीः नेशनल बुक ट्रस्ट।
3. नायक, ह. (2023). न्च् और डिजिटल लेनदेन की संरचना. अर्थशास्त्र शोध पत्रिका, 12(4), 61–70।

4. वर्मा, र. (2024). डिजिटल समावेशन की बाधाएँ. सामाजिक दृष्टिकोण, 19(1), 22–31।
5. मिश्रा, ए. (2021). डिजिटल भुगतान का इतिहास और भारत में प्रभाव. नई सोच, 15(3), 49–58।
6. श्रीवास्तव, अ. (2023). विमुद्रीकरण और डिजिटल साक्षरता. भारतीय समाजशास्त्र पत्रिका, 20(2), 65–72।
7. राणा, न. (2024). ग्रामीण भारत और नकदी रहित व्यवस्था. ग्रामीण विकास पत्रिका, 14(2), 38–47।
8. तिवारी, प. (2022). ळ20 देशों में डिजिटल लेनदेन की तुलना. भारत–वैश्विक अध्ययन, 11(1), 50–59।
9. सेन, स. (2023). डिजिटल इंडिया और वैश्विक परिप्रेक्ष्य. नई दिल्लीः सेंटर फॉर डिजिटल पॉलिसी।
10. दुबे, म. (2023). डिजिटल साक्षरता और ग्रामीण युवा. शिक्षा संवाद, 18(1), 40–48।
11. जोशी, व. (2022). साइबर सुरक्षा और नकदी रहित भुगतान. सुरक्षा अध्ययन समीक्षा, 13(2), 33–41।
12. बंसल, प. (2024). डिजिटल जागरूकता में लिंग विभाजन. नारी विमर्श, 21(1), 28–35।
13. कुलश्रेष्ठ, प. (2021). ऑनलाइन लेन–देन में धोखाधड़ी और समाधान. उपभोक्ता संरक्षण जर्नल, 16(3), 55–64।
14. अग्रवाल, क. (2023). न्च् 2.0 का सामाजिक प्रभाव. भारतीय बैंकिंग समीक्षा, 19(2), 43–52।
15. कुमार, वी. (2024). मोबाइल बैंकिंगः वर्तमान और भविष्य. डिजिटल वित्त शोध पत्रिका, 17(1), 35–42।
16. यादव, स. (2023). ग्रामीण व्यापारियों में डिजिटल अनिच्छा. ग्रामीण बाजार अध्ययन, 9(2), 22–30।
17. पटेल, जे. (2022). नकदी रहित लेन–देन और व्यवहारिक बाधाएँ. मनोविज्ञान और समाज, 14(1), 40–49।
18. सक्सेना, टी. (2023). छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण. लघु उद्योग संवाद, 12(3), 36–44।
19. भारद्वाज, र. (2021). डिजिटल भुगतानों की नीतिगत समीक्षा. नीति दर्शन, 10(2), 50–58।
20. मेहता, अ. (2024). ग्रामीण भारत में फत् कोड की भूमिका. तकनीकी समावेशन शोध, 7(1), 25–34।

❑❑❑